अर्थव्यवस्थाःसंभावनाओं से लबरेज भारत

जयंतीलाल भंडारी

यद्यपि एक ओर भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक आर्थिक सुस्ती और कोरोना प्रकोप का संकट दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी ओर दुनिया के कई प्रमुख आर्थिक संगठनों की रिपोटरे में भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने की संभावनाएं पेश की जा रही हैं।

कहा जा रहा है कि आर्थिक सुस्ती के बाद भी बीते वर्ष 2019 में चुनौतियों के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में आगे बढ़ी है। ऐसे में इस वर्ष 2020 में भी उपयुक्त रणनीतिक कदमों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने की संभावनाएं रखती है।

गौरतलब है कि हाल में 18 फरवरी को प्रसिद्ध अमेरिकी थिंक टैंक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू द्वारा प्रकाशित दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग रिपोर्ट-2019 के अनुसार भारत 209 लाख करोड़ रुपये सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की ऊंचाई को छूते हुए ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़कर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का 60 फीसदी योगदान हो गया है। अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी क्रमशः पहले से चौथे क्रम की अर्थव्यवस्थाओं के रूप में चिह्नित किए गए हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने में तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार की भी अहम भूमिका है। हाल में प्रकाशित विश्व विख्यात संगठन ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म के प्राइस वॉटरहाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) सर्वे के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे चमकीला बाजार बन गया है, और 2020 में भारत के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। ऐसे में बढ़ते हुए भारतीय बाजार पर दुनिया की निगाहें लगी हैं।

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अप्रैल से नवम्बर माह के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 24.4 अरब डॉलर प्राप्त हुआ जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी समान अवधि में 21.1 अरब डॉलर था। इसी तरह से चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 की अप्रैल से नवम्बर की अवधि में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की मद में 12.6 अरब डॉलर की रकम आई जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी समान अवधि में 8.7 अरब डॉलर थी। इसमें कोई दोमत नहीं है कि इस समय भारतीय बाजार में नवाचार, कारोबार सुधार, उत्पादन और सर्विस क्षेत्र में सुधार की उभरती हुई प्रवृत्ति रेखांकित हो रही है। पिछले दिनों 4 एवं 5 फरवरी को प्रकाशित भारत के मैन्युफैक्चरिंग का हाल बताने वाले परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का हाल बताने वाले सर्विसेस बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स ने बढ़त दिखाई है। दिसम्बर, 2019 में यह इंडेक्स 52.7 पर था, जो जनवरी, 2020 में बढ़कर 55.3 पर पहुंच गया है, जबकि सर्विसेस इंडेक्स, जो दिसम्बर, 2019 में 53.3 था, जनवरी, 2020 में बढ़कर 55.5 अंक पर रहा।

माना जाता है कि यदि यह इंडेक्स 50 से ऊपर है, तो यह न केवल अर्थव्यवस्था विस्तार, उत्पादन और सेवा क्षेत्र वृद्धि का संकेत है, बल्कि अनुकूल बाजार, नई मांग, बिक्री, कच्चे माल की खपत और रोजगार बढ़ने का भी संकेत है।

इसी तरह हाल में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रमुख क्रिस्टालिना जार्जीवा ने दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच, 2020 को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट अस्थायी है और शीघ्र ही यह सुस्ती के दौर से बाहर आ सकती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के सुस्ती के दौर से बाहर आने की संभावनाएं बताने वाले प्रसिद्ध वैंकि मीडिया समूह ब्लूमबर्ग ने ताजा रिपोर्ट में कहा कि अगस्त, 2019 के बाद के पांच महीनों में अर्थव्यवस्था के 8 में से 5 सूचकांकों पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन सुधरते दिखाई दे रहा है। विगत पांच महीनों में सर्विस सेक्टर की गतिविधियां बढ़ी हैं। औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। बिजनेस एक्टिविटी बढ़ी हैं। कर्ज की मांग बेहतर हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार 475 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर है। शेयर बाजार भी संतोषजनक है।

बजट से अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर होगा। निस्संदेह भारतीय बाजार में कारोबार में बढ़ती अनुकूलताओं के कारण ख्याति प्राप्त वैंकि फायनेंस और कॉमर्स कंपनियां भारत में अपने कदम तेजी से बढ़ा रही हैं। इतना ही नहीं भारत से कई विकसित और विकासशील देशों के लिए कई काम बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग पर हो रहे हैं। भारत में स्थित वैंकि फाइनेंशियल फर्मो के दफ्तर ग्लोबल सुविधाओं से सुसज्जित हैं। देश में बढ़ते नवाचार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप, विदेशी निवेश, रिसर्च एंड डवलपमेंट के कारण भारतीय बाजार का विस्तार होता गया है।

काम की भूख और उत्सुकता के कारण आगे बढ़ती रही : लारा दत्ता

अभिनेत्री लारा दत्ता का कहना है कि चीजों को लेकर उनकी भूख और उत्सुकता के कारण ही साल 2000 में मिस यूनीवर्स का खिताब जीतने के समय से लेकर अब तक वह लगातार आगे बढ़ती रही हैं। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले एयरबीएनबी ने अपने एक प्रचार समारोह में महिला उद्यमियों के जोश व जुनून का जश्न मनाया और इस मौके पर मीडिया से बातचीत में लारा ने कहा, मेरे ख्याल से यह सिर्फ भूख और उत्सुकता है। कभी भी किसी एक चीज तक खुद को सीमित रखने का ख्याल मुझमें नहीं आया। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं केवल एक ब्यूटीचीन या अभिनेत्री हूं। इनसे संबंधित काम के बाद मुझे कुछ और नए की तलाश रहती है और इसी के कारण मेरा आगे बढ़ना जारी रहा है। बॉलीवुड में आने से पहले लारा ने साल 2000 में सौन्दर्य प्रतियोगिता में अपना परचम लहराया था। अभिनय के अलावा वह एक पत्नी और एक मां भी हैं। उन्होंने फिल्म प्रोड्क्शन के क्षेत्र में भी कदम रखा है। लारा ने कई कार्यक्रमों की मेजबानी भी की है और इसके साथ ही वह मिस इंडिया की प्रतियोगियों की सलाहकार भी रही हैं। साल 2019 में लारा ने एरियस नामक अपने सौन्दर्य उत्पादों को लॉन्च किया, जो पूरी तरह से पशु क्रूरता रहित है।

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

कॉम्पटिशन से फर्क नहीं पड़ता हैः जाह्नवी

बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर का कहना है कि उन्हें कॉम्पटिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाह्नवी ने कहा कि उन्हें कॉम्पटिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह जानती हैं कि वह इंडस्ट्री को क्या दे सकती हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि वह अपनी किन चीजों पर काम कर एक बेहतर एक्टर बन सकती हैं और इसके लिए लगातार मेहनत कर रही हैं। इंडस्ट्री में सभी के लिए स्पेस है। जाह्नवी ने कहा, पिछले एक साल से मेरी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है और जाहिर है मेरी समकालीन अभिनेत्रियों के साथ तुलना होगी ही लेकिन कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वह दूसरे कलाकारों का काम देखकर काफी मोटिवेट होती हैं और उनसे सीखने की कोशिश करती हैं। जाह्नवी ने कहा कि वे सिनेमैटिक स्पेस का हिस्सा बनकर काफी खुश हैं। वह फिल्म दोस्ताना 2 की शूटिंग करने जा रही हैं। जाह्नवी कपूर इसके अलावा फिल्म रूहीआफजा में भी काम कर रही हैं। वह फिल्म दि कारगिल गर्ल को लेकर भी चर्चा में हैं। यह फिल्म कारगिल युद्ध के समय वायु सेना का विमान उड़ाने वाली पायलट गुंजन सक्सेना की लाइफ पर आधारित है।

सू- दोकू क्र.065

	9		1	6		2		7
3								
		6					9	
7			5		1		3	
	8			9		6		2
		4					7	
	3				2	9		6
6		7	3					4
	4			1		7	8	

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.64का हल

2	6	3	9	8	7	1	5	4
8	5	1	3	2	4	6	7	9
9	4	7	1	5	6	8	2	3
3	9	8	6	7	1	5	4	2
6	1	2	5	4	3	9	8	7
5	7	4	8	9	2	3	1	6
1	2	6	7	3	5	4	9	8
4	8	5	2	6	9	7	3	1
7	3	9	4	1	8	2	6	5

मुद्दा : निर्माण मजदूरों की सुनवाई जरूरी

भारत डोगरा

रोजगार सृजन की दृष्टि से भारत में निर्माण उद्योग का विशेष महत्त्व रहा है।

हमें बताया गया है कि कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार हमारे देश में निर्माण क्षेत्र में है। यह हमें देखने को भी मिलता है। कृषि संकट की स्थिति में बहुत से किसानों और खेत-मजदूरों को भी निर्माण क्षेत्र में ही अतिरिक्त मजदूरी मिलती है। जाहिर है कि निर्माण मजदूरों का अर्थव्यवस्था में बेहद महत्त्वपूर्ण स्थान है। उनके इसी महत्त्व को देखते हुए निर्माण श्रमिकों की भलाई के लिए दो कानून वर्ष 1996 में बनाए गए थे। इन कानूनों के अनुसार निर्माण कार्यों पर उपकर या सेस लगाया गया और निर्माण मजदूरों के लिए हर राज्य में बोर्ड बनाया गया जिसने इस उपकर से प्राप्त धनराशि का उपयोग निर्माण मजदूरों की भलाई के अनेक कार्यों के लिए किया।

इस तरह जून, 2018 तक 37483 करोड़ रुपये निर्माण मजदूरों की भलाई के लिए एकत्र हुए जिस पर बहुत सा ब्याज भी एकत्र हुआ। इसके तहत 2.87 करोड़ मजदूरों का पंजीकरण हुआ। एक करोड़ से अधिक मजदूरों को पेंशन, बच्चों की शिक्षा, मातृत्व लाभ, दुर्घटना सहायता आदि के लिए 9492 करोड़ रुपये दिए गए। अभी एकत्रित राशि और उसके ब्याज के एक बड़े भाग का उपयोग होना है। वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने इन दोनों कानूनों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिए थे। उसके बाद उम्मीद बनी थी कि निर्माण मजदूरों की स्थिति बेहतर हो सकेगी। लेकिन सारे किए-धरे पर नये लेबर कोड ने पानी फेर दिया। रही-सही कसर कुछ अन्य कारणों के चलते पैदा हुई अनिश्चय की स्थिति ने पूरी कर दी। विशेषकर दिल्ली में बहुत से मजदूरों की पेंशन, बच्चों की छात्रवृत्ति आदि लाभ रुक गए हैं।

दिल्ली की एक मजदूर बस्ती (बवाना जे जे कालोनी, पार्ट 1 और 2) में पूछने पर पता चला कि केवल एक बस्ती में 100 से अधिक बुजुर्ग निर्माण मजदूरों की पेंशन पांच महीनों से रुकी पड़ी है और 22 मजदूरों की पेंशन 15 महीनों से नहीं मिली है। भ्रष्टाचार के कारण मजदूर हकदारी में अधिक मेहनत और ईमानदारी से लगे मजदूर संगठनों के सात ही अधिक अन्याय हो रहा है। पहले भ्रष्टाचार के कारण ही उन्हें वंचित किया गया। फिर शिकायत करने पर कहा गया कि अभी तो भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। अतः कोई लाभ देने पर रोक जारी है। इस तरह के बहानों से मजदूरों की भलाई के लिए एकत्र पैसे को उन तक पहुंचने से रोका जा रहा है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है।

निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति ने 12 फरवरी को जारी किए गए एक बयान में कहा है कि 30 अक्टूबर, 2018 को केंद्रीय श्रम सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर आधारित कार्य योजना और आदर्श कल्याण योजना भेजते हुए इसे गम्भीरता से लागू करने के लिए लिखा था। लेकिन 16 नवम्बर, 2018 को ही केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पर लेबर कोड का तीसरा स्वरूप घोषित कर दिया जिसमें 1996 के निर्माण मजदूरों के कानूनों का भविष्य अनिश्चित करने की तैयारी भी शामिल है। ऐसे अनेक मजदूरों के लिए पेंशन रुक जाने के कारण भूख, तनाव और दवाभाव के कारण मौत की संभावना भी उपस्थित हो गई है। अतः इस संदर्भ में बहुत शीघ्र ही असरदार कार्यवाही करके मजदूरों को जल्द से जल्द न्याय दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही ऐसे जरूरी कदम भी उठाने चाहिए जिनसे निर्माण मजदूरों की भलाई के लिए जो कानून 1996 से चले आ रहे हैं, वे बने रहें तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इन कानूनों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी जरूरी कदम भी शीघ्र से शीघ्र उठाने चाहिए। यदि ऐसा होगा तो लगभग 30,000 करोड़ रुपये का लाभ शीघ्र ही देशभर के निर्माण मजदूरों को निकट भविष्य में मिल सकेगा।